

## डिजिटल अरेस्ट

### प्रलिमिस के लिये:

डिजिटल अरेस्ट, CBI, प्रवरतन निदिशालय, नारकोटिक्स बयरो, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, CBDC, क्रपिटोकरेंसी, राष्ट्रीय साइबर अपराध रपोर्टिंग पोर्टल, वरचुअल प्राइवेट नेटवर्क, पॉजी या परिमित योजनाएँ, राष्ट्रीय साइबर अपराध हेलप्लाइन, आधार

### मेन्स के लिये:

साइबर धोखाधड़ी की आरथकि लागत, संबंधित जोखिम एवं आगे की राह।

स्रोत: द हिंदू

### चर्चा में क्यों?

डिजिटल अरेस्ट साइबर स्कैम का सबसे नवीन रूप है जिससे वर्ष 2024 में 92,000 से अधिक भारतीय प्रभावित हुए हैं, जिसमें कर या कानूनी बकाया को हल करने की आड़ में ऑनलाइन अंतरण के माध्यम से धन नकाला जाता है।

### डिजिटल अरेस्ट के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- डिजिटल अरेस्ट घोटाले में साइबर अपराधी विधिप्रवरतन अधिकारियों या सरकारी एजेंसियों जैसे राज्य पुलसि, CBI, ED और नारकोटिक्स बयरो की नकली पहचान बनाकर आम लोगों से ठगी करते हैं।
  - घोटालेवाज लोग बनियां करते हैं कि उनके खलिफ मामला दर्ज किया गया है तथा अपने आरोपों को विश्वसनीय बनाने के लिये वे फेक पुलसि थाने का भी इस्तेमाल करते हैं।
- साइबर अपराधी फोन या ईमेल के माध्यम से पीड़ितों से संपर्क करते हैं। ये शुरुआत ऑडियो कॉल से करते हैं और फिर हवाई अड्डों, पुलसि स्टेशनों या न्यायालयों जैसे स्थानों से वीडियो कॉल करते हैं।
  - ये वैध दखिने के लिये अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पुलसि अधिकारियों, वकीलों और न्यायाधीशों की तस्वीरों को डिस्प्ले पक्षिकार के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
  - ये ईमेल या मैसेजिंग ऐप के माध्यम से फेक गरिफ्तारी वारंट, कानूनी नोटसि या आधिकारिक दखिने वाले दस्तावेज़ भी भेज सकते हैं।
- पीड़ितों को फँसाना: साइबर अपराधी आमतौर पर पीड़ितों पर गंभीर अपराधों जैसे धन शोधन, मादक पदारथों की तस्करी या साइबर अपराध का आरोप लगाते हैं।
  - वे अपने आरोपों को विश्वसनीय बनाने के लिये नकली साक्ष्य बना सकते हैं।
- लोगों की भेदभावता:
  - भय और घबराहट: गरिफ्तारी की धमकी या भय से पीड़ित बनियां सोचे-समझे ऐसे लोगों की बात सही मान लेते हैं।
  - जानकारी का अभाव: विधिप्रवरतन प्रक्रियाओं से अनभिज्ञता के कारण पीड़ितों के लिये वैध दावों और धोखाधड़ी के बीच अंतर करना कठनी हो जाता है।
  - सामाजिक कलंक: सामाजिक कलंक एवं परवार पर पड़ने वाले प्रभाव के डर से पीड़ित ठगी का शकिर होते हैं।
  - तकनीक का प्रयोग: विश्वसनीय दखिने के लिये इसमें AI आवाज़ों, पेशेवर लोगों और नकली वीडियो कॉल का उपयोग किया जाता है।
  - तकनीकी संवेदनशीलता: तकनीकी की कम जानकारी रखने वाले या तनावग्रस्त व्यक्तिआसानी से धोखाधड़ी का शकिर हो जाते हैं।

### भारत में 'साइबर स्कैम' की स्थितिक्रिया है?

- अवलोकन: भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के अनुसार, भारत में साइबर स्कैम/साइबर धोखाधड़ी की आवृत्ति और वित्तीय प्रभाव दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
  - यह चतिअनक प्रवरततभारत के डिजिटल पारस्थितिकी तंत्र में लगातार बढ़ते खतरे का संकेत देती है।
- शकियतें और नुकसान: पछिले कुछ वर्षों में शकियतों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वर्ष 2021 में 1,35,242, वर्ष 2022 में 5,14,741

और वर्ष 2023 में 11,31,221 शक्तियों दर्ज की गई हैं।

◦ वर्ष 2021 से सत्रिवर, 2024 के बीच साइबर स्कैम से कुल मौद्रिक नुकसान 27,914 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।

■ प्रमुख स्कैम:

- स्टॉक ट्रेडिंग स्कैम: 2,28,094 शक्तियों से 4,636 करोड़ रुपए की हानि के साथ यह नुकसान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है।
    - स्कैम करने वाले इसका उपयोग इक्विटी, विदेशी मुद्रा या करपिटोकरेसी का व्यापार करते समय अतारकिं लाभ का वादा करने के लिये करते हैं, लेकिन पीड़ित अंततः धोखे का शक्तिर हो जाते हैं।
  - पॉजी स्कैम स्कैम: 1,00,360 शक्तियों के कारण 3,216 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
  - "डिजिटल अरेस्ट" धोखाधड़ी: 63,481 शक्तियों से 1,616 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
- धन के धोखाधड़ी की नई रणनीति: साइबर अपराधियों ने धन के धोखाधड़ी के लिये अपनी रणनीतियाँ अपना ली हैं।
- नकासी के तरीके: चोरी किये गए पैसे अक्सर विभिन्न चैनलों के माध्यम से नकाले जाते हैं, जिनमें चेक, CBDC, फिनिटेक करपिटोकरेसी, ATM, मर्चेंट पेमेंट और ई-वॉलेट शामिल हैं।
  - मुले अकाउंट (Mule Accounts): I4C ने लगभग 4.5 लाख मुले अकाउंट की पहचान की है और उन्हें फ्रीज कर दिया है, जिनका उपयोग मुख्य रूप से साइबर अपराध से धन शोधन के लिये किया जाता था।

## भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C):

- परिचय: I4C को गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में 'साइबर स्कैम सहति सभी प्रकार के साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वयित तरीके से नपिटने के लिये लॉन्च किया गया था।
- I4C के उद्देश्य:
  - देश में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिये एक नोडल नकाय के रूप में कार्य करना।
  - महलियों और बच्चों के विद्युदध साइबर अपराध के विद्युदध लड़ाई को मजबूत करना।
  - साइबर अपराध से संबंधित शक्तियों को आसानी से दर्ज करने और साइबर अपराध की परवृत्तियों और पैटर्न की पहचान करने में सुविधा प्रदान करना।
  - सक्रिय साइबर अपराध की रोकथाम और पता लगाने के लिये कानून प्रवरतन एजेंसियों के लिये एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करना।
  - साइबर अपराध को रोकने के बारे में जनता में जागरूकता उत्पन्न करना।
  - साइबर फोरेंसिक, जाँच, साइबर सचिवालय, साइबर अपराध विज्ञान आदि के क्षेत्र में पुलसि अधिकारियों, सरकारी अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों की क्षमता निर्माण में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करना।
- राष्ट्रीय साइबर अपराध रपिरेटिंग पोर्टल:
  - I4C के तहत, [राष्ट्रीय साइबर अपराध रपिरेटिंग पोर्टल](#) एक नागरिक-केंद्रित पहल है जो नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी की ऑनलाइन रपिरेट करने में सक्षम बनाएगी और सभी शक्तियों तक संबंधित कानून प्रवरतन एजेंसियों द्वारा विधि के अनुसार कारबाई करने के लिये पहुँच सुनिश्चिति की जाएगी।

## साइबर स्कैम के नपिटान हेतु क्या चुनौतियाँ हैं?

- गोपनीयता: साइबर अपराधी अपनी पहचान और स्थान को छपाने के लिये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPNA) और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप जैसे उपकरणों का उपयोग करते हैं, जिससे उन्हें पता लगाने और गरिफ्तार करने के प्रयास जटिल हो जाते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय दायरा: साइबर स्कैम अक्सर कई देशों तक फैले होते हैं, जिससे स्थानीय कानून प्रवरतन एजेंसियों के लिये कारबाई करना मुश्किल हो जाता है।
- स्कैम का एक बड़ा हसिसा दक्षणि प्रव एशिया और चीन से आता है।
- तेज़ी से विकसित हो रही रणनीतियाँ: फिशिंग घोटाले ईमेल के माध्यम से अधिक प्रष्टकृत तरीकों से किये जाते हैं, जिनमें सोशल इंजीनियरिंग, टेक्स्ट मैसेज और वॉयस कॉल शामिल हैं, जिससे धोखाधड़ी का पता लगाना कठिन हो गया है।
- उन्नत मैलवेयर: साइबर स्कैम उन्नत मैलवेयर का उपयोग करते हैं जो डेटा चोरी करने या अनधिकृत पहुँच प्राप्त करने के लिये इंटीवायरस प्रोग्राम और फायरवॉल को बायपास कर सकते हैं।
- वनियिमक खिंडन: विभिन्न देशों के अलग-अलग नियम हैं, जिससे साइबर अपराध से नपिटने के लिये सुसंगत अंतर्राष्ट्रीय रणनीतियाँ बिनाना कठिन हो जाता है।
  - इसके अलावा, देशों के पास डेटा साझा किये बनाना उभरते साइबर स्कैम के उझान और रणनीतियों की पहचान करने के लिये व्यापक खतरा खुफिया जानकारी का अभाव है।
- बढ़ता डिजिटल बाज़ार: [ई-कॉमर्स](#) और [डिजिटल भुगतान प्रणालियों](#) के विकास के कारण फेक ऑनलाइन स्टोर, कार्ड स्कीमिंग और धोखाधड़ी भुगतान योजनाओं जैसे स्कैम में वृद्धि हुई है।

## साइबर स्कैम के प्रकार

- फिशिंग स्कैम: धोखेबाज़, विश्वसनीय संगठनों की नकल करते हुए नकली ईमेल या संदेश भेजते हैं, ताकि पीड़ितों से पासवर्ड या वित्तीय विवरण जैसी संवेदनशील जानकारी साझा करवा सकें।
- लॉटरी और पुरस्कार स्कैम: पीड़ितों को सूचना मिलती है कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण पुरस्कार जीता है और उसे प्राप्त करने के लिये उनसे प्रोसेसिंग शुल्क या कर का भुगतान करने के लिये कहा जाता है।
- भावनात्मक हेरफेर स्कैम: डेटाग्रे ऐप्स पर स्कैमर पीड़ितों के साथ संबंध बनाते हैं और बाद में आपात स्थितियों के लिये पैसे मांगते हैं,

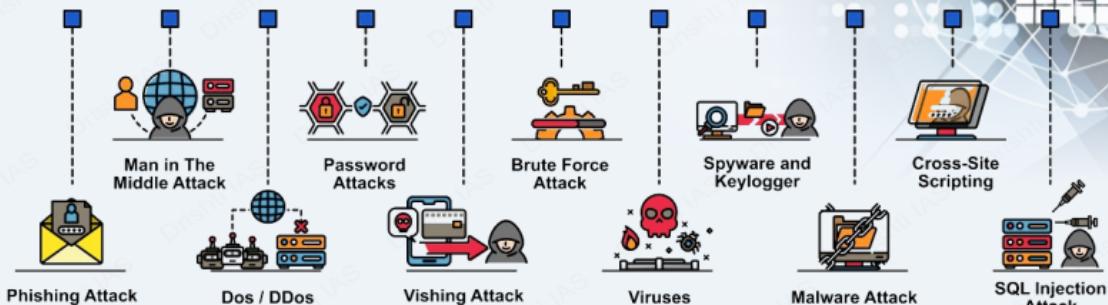
- अक्सर क्रपिटोकरेंसी में भुगतान की मांग करते हैं।
- **जॉब स्कैम :** स्कैमर जॉब चाहने वालों, वरिष्ठ रूप से नए स्नातकों को व्यक्तिगत जानकारी या पैसा देने के लिये भ्रती प्लेटफार्मों या सोशल मीडिया पर फेक जॉब लिस्टिंग पोस्ट करते हैं।
  - **नविश स्कैम :** ये स्कैम [पॉजी या परिमिडि योजनाओं](#) के माध्यम से उच्च, अवास्तविक रटिरन का बादा करके पीड़िति की त्वरित धन कमाने की इच्छा को आकर्षित करते हैं।
  - **कैश-ऑन-डिलीवरी (CoD) स्कैम :** स्कैमर नकली ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं जो CoD ऑर्डर स्वीकार करते हैं। जब उत्पाद डिलीवर किया जाता है, तो यह या तो नकली होता है या वजिज्ञापति के अनुसार नहीं होता है।
  - **फेक चैरटी अपील स्कैम :** स्कैमर आपदा राहत या सावास्थय पहल जैसे अनुपयुक्त कारणों के लिये फेक वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज बनाते हैं, तथा तात्कालिकता और सहानुभूति पैदा करने के लिये भावनात्मक कहानियाँ या छवियों का उपयोग करते हैं।
  - **गलत तरीके से धन-हस्तांतरण स्कैम :** स्कैमर पीड़ितों से संपर्क कर दावा करते हैं कि उनके खाते में गलती से धन भेज दिया गया है, तथा कानूनी परेशानी से बचने के लिये धन वापस करने के लिये उन पर दबाव डालने के लिये फेक लेनदेन रसीदों का उपयोग करते हैं।
  - **क्रेडिट कार्ड स्कैम :** स्कैमर कम ब्याज दरों पर ऋण की पेशकश करते हैं और उसे तुरंत मंजूरी दे देते हैं। पीड़िति द्वारा ऋण सुरक्षित करने के लिये अग्रमि शुल्क का भुगतान करने के बाद, स्कैमर गायब हो जाते हैं।



# साइबर सुरक्षा

साइबर सुरक्षा, साइबर हमलों को रोकने या उनके प्रभाव को कम करने के लिये किसी भी तकनीक, उपाय या अभ्यास को संदर्भित करती है।

## CYBER SECURITY ATTACKS



NCRB की "भारत में अपराध" रिपोर्ट, 2022 के अनुसार, वर्ष 2021 के बाद से भारत में साइबर अपराध 24.4% बढ़ गए हैं।

## सामान्य साइबर सुरक्षा मिथक

- केवल मज़बूत पासवर्ड ही पर्याप्त सुरक्षा है
- प्रमुख साइबर सुरक्षा जोखिम सर्वविदित हैं
- सभी साइबर हमले वैक्टर (vector) निहित होते हैं
- साइबर अपराधी छोटे व्यवसायों पर हमला नहीं करते हैं

## साइबर वार

- किसी दूसरे के कंप्यूटर सिस्टम को बाधित करने, क्षति पहुँचाने या नष्ट करने के लिये किये गए डिजिटल हमले।

## CYBER THREAT ACTORS

CYBER THREAT ACTOR	MOTIVATION
NATION-STATES	GEOPOLITICAL
CYBERCRIMINALS	PROFIT
HACKTIVISTS	IDEOLOGICAL
TERRORIST GROUPS	IDEOLOGICAL VIOLENCE
THRILL-SEEKERS	SATISFACTION
INSIDER THREATS	DISCONTENT

## साइबर सुरक्षा के प्रकार

- महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा सुरक्षा (रोबस्ट एक्सेस कंट्रोल)
- नेटवर्क सुरक्षा (डिजिटल फायरवॉल)
- एण्डिकेशन सुरक्षा (कोड रिव्यू)
- क्लाउड सुरक्षा (टोकनाइजेशन)
- सूचना सुरक्षा (डेटा मासिंग)



## हाल ही में हुए प्रमुख साइबर हमले

- वाताक्रांति रैनमधेय अटैक (वर्ष 2017)
- कैब्रिज एनालिटिका डेटा ब्रीच (वर्ष 2018)
- 9M+ कार्डधारकों का वित्तीय डेटा लीक, जिसमें SBI भी शामिल है (वर्ष 2022)

## विनियम एवं पहलें

### अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर:

- साइबर स्पेस में राज्यों के उत्तरदायी व्यवहार को बढ़ावा देने से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के सरकारी विशेषज्ञों के समूह (GGE)
- नाटो का कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CCDCOE)
- साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन, 2001 (भारत हस्ताक्षरकर्ता नहीं है)

### भारतीय स्तर पर:

- IT अधिनियम, 2000 (धारा 43, 66, 66B, 66C, 66D)
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013
- नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, 2020
- साइबर सुरक्षित भारत पहल
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)
- कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम - भारत (CERT-In)

## साइबर सुरक्षा के लिये उठाए जाने वाले आवश्यक कदम

- नेटवर्क सुरक्षा
- मैलवेयर सुरक्षा
- इंसिडेंट मैनेजमेंट
- उपयोगकर्ता को शिक्षित और जागरूक करना
- सुरक्षित विद्युत
- उपयोगकर्ता के विशेषाधिकारों का प्रबंधन करना
- सूचना जोखिम प्रबंधन व्यवस्था

**भारत में साइबर स्कैम से संबंधित प्रमुख सरकारी पहल क्या हैं?**

- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति
  - कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम - भारत (CERT-In)
  - साइबर सुरक्षति भारत पहल
  - साइबर सवच्छता केंद्र
  - राष्ट्रीय महत्वपूरण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC)
  - डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023
  - साइबर अपराध समनव्य केंद्र
  - नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली

आगे की राह

- **डिजिटल सुरक्षा:** भारत के प्रधानमंत्री ने डिजिटल अरेस्ट से बचाव के लिये एक सरलतीन-चरणीय सुरक्षा प्रोटोकॉल की रूपरेखा प्रस्तुत की।
    - वरिम: शांत रहें एवं त्वरति व्यक्तिगत जानकारी देने से बचें।
    - विद्यार करना: ध्यान रखें कि विधिक एजेंसियाँ कॉल के माध्यम से ऐसी पूछताछ नहीं करती हैं या कॉल के माध्यम से भुगतान की मांग नहीं करती हैं।
    - कार्रवाई करना: राष्ट्रीय साइबर अपराध हेलप्लाइन (1930) या राष्ट्रीय साइबर अपराध रपोर्टिंग पोर्टल पर घटनाओं की रपोर्ट करना, परविार के सदस्यों को सूचित करना एवं साक्ष्य दर्ज करना।
  - **साइबर सुरक्षा के सर्वोत्तम अभ्यास:** फायरबॉल का उपयोग करना, जो कंप्यूटरों के लिये सुरक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में कार्य करते हैं, अनधिकृत पहुँच को रोकने के लिये नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और फ़िल्टर करते हैं।
    - सुरक्षा संबंधित कमर्यों को दूर करने के लिये सभी सॉफ्टवेयर और हारडवेयर प्रणालयों को अद्यतन रखना।
  - **उन्नत सुरक्षा:** सुरक्षा की एक अतिरिक्त स्तर जोड़ने के लिये टू-फैक्टर प्रमाणीकरण लागू करना। वित्तीय रकिर्ड सहति संवेदनशील डेटा की सुरक्षा के लिये एन्क्रिप्शन का उपयोग करना।
  - **सतरकता में वृद्धि:** दैंकों को कम शेष वाले या वेतनभोगी खातों में उच्च मूल्य के लेनदेन की निगरानी करनी चाहयि तथा प्राधिकारियों को सचेत करना चाहयि, क्योंकि चोरी का पैसा अक्सर इन खातों में स्थानांतरित कर दिया जाता है तथा उसके बाद उसके क्रपिटोकरेंसी में परविर्तति कर दिश भेज दिया जाता है।
  - **जागरूकता:** कोई भी व्यक्तिगत जानकारी (जैसे आधार या पैन कार्ड विवरण) एवं पैसा न देना।
    - हमेशा आधिकारिक चैनलों के माध्यम से कॉल करने वाले की पहचान स्वतंत्र रूप से सत्यापिति करना।
    - सामान्य धोखाधड़ी की रणनीति के बारे में जानें और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये इस जानकारी को अपने परविार और दोस्तों के साथ साझा करना।
  - **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** समान कानून बनाने, खुफया जानकारी साझा करने और प्रतिक्रियाओं में समन्वय स्थापित करने के लिये राष्ट्रों के बीच सहयोग से सीमा पार साइबर अपराध से निपटने में सहायत मिल सकती है।

**परशन:** साइबर स्कैम के वभिन्न प्रकार क्या हैं? साइबर स्कैम से नपिटने में क्या चूनौतियाँ विद्यमान हैं?

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

????????????

प्रश्न. भारत में, कर्सी व्यक्तिके साइबर बीमा कराने पर, नधिकी हानिकी भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त

नमिनलखिति में से कौन-कौन से लाभ दिये जाते हैं? (2020)

1. यदि कोई कसी मैलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुँच को बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचालित करने में लगने वाली लागत
  2. यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि कसी शरारती तत्त्व द्वारा जानबूझ कर कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाया गया है तो एक नए कंप्यूटर की लागत
  3. यदि सिइबर बलात्-ग्रहण होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिये वैशिष्ट प्रामर्शदाता की की सेवाएँ पर लगने वाली लागत
  4. यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1,2 और 4  
 (b) केवल 1, 3 और 4

- (c) केवल 2 और 3  
(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

प्रश्न. भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रपोर्ट करना नमिनलखिति में से कसिके/कनिके लायि वधिति: अधिकारिक है? (2017)

1. सेवा प्रदाता
2. डेटा सेंटर
3. कॉर्पोरेट नियम

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनायिः

- (a) केवल 1  
(b) केवल 1 और 2  
(c) केवल 3  
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

**?/?/?/?/?**

प्रश्न: साइबर सुरक्षा के वभिन्न तत्त्व क्या हैं? साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा कीजिये कि भारत ने कसि हद तक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति सफलतापूर्वक वकिसति की है। (2022)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rising-digital-arrests>